लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 1 - 15 अक्तूबर, 2022 www.haryanasamvad.gov.in अंक -51

"सहनशील होना अच्छी बात है लेकिन अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है।

: जयशंकर प्रसाद

विदेशी निवेश से खुल रहे प्रगति के नए द्वार

3

किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का लक्ष्य

4

राखीगढ़ी को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान

7

जन संवाद

विशेष प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संकल्प है कि प्रदेश के लोगों का जीवन सहज व सरल हो तथा हर परिवार आत्मनिर्भर बने ताकि 'आजादी का अमृत महोत्सव' सही मायने में सार्थक हो सके। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा हर नागरिक तक पहुंचे इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं। इन सेवाओं में कोई कोताही न हो तथा लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान हो इसके लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं लोगों से रूबरू होने के लिए 'जन संवाद' कार्यक्रम शुरू किया है।

करनाल, रोहतक व सिरसा में तीन सफल कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। स्थानीय लोगों ने इन कार्यक्रमों के जरिए सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याओं का जिक्र किया है जिनमें से अधिकांश का तत्काल समाधान हुआ है। सेवाओं में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों या अधिकारियों को मौके पर दंडित भी किया गया है।

जन संवाद कार्यक्रमों में न केवल सामूहिक मसलों को ही सुना जा रहा है बल्कि व्यक्तिगत समस्याओं को भी सम्मान दिया जा रहा है। वह चाहे सम्मान पेंशन का मामला हो या बिजली-पानी से संबंधित। ग्रामीण क्षेत्र में अमृत सरोवर योजना की राह में कुछ बाधाएं हैं जिनको दूर करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिन तालाबों में पानी भरा है उन्हें जल्द से जल्द खाली कराने के लिए कहा गया है। जहां-जहां अवैध कब्जे हैं, जिला प्रशासन सख्ती से पेश आकर उन कब्जों को बहाल कराए।

नहरों से पानी चोरी के मामलों की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार टेल तक पानी पहुंचाने के लिए दृढ़संकल्प है। इस तरह की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए। किसानों से आह्वान किया कि जहां पानी की कठोरता है वहां फव्वारा विधि से सिंचाई की जाए । इसमें 85 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में छोटी-मोटी अनेक समस्याएं होती हैं, जिनमें से सभी का वर्णन करना आसान नहीं होता। इसके सहज समाधान के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल व नगर दर्शन पोर्टल की व्यवस्था की गई है। नागरिकों से आग्रह है कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं का इन पोर्टल पर अवश्य जिक्र करें। वह शिकायत संबंधित विभाग के पास तत्काल पहुंच जाती है तथा उसका प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाता है।

युग-परिवर्तन का दौर

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज का दौर युग-परिवर्तन का दौर है। ऐसे में बहुत सी सेवाएं आनलाइन हो रही हैं। ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार भी उसी का हिस्सा है। अब किसान अपनी फसल इसके माध्यम से केरल से असम तक के व्यापारी को बेच सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उत्थान की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। राज्य में एक लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले 30 हजार परिवारों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं। 50 हजार सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम इकाइयों के माध्यम से रोजगार सृजन किया गया है तथा डेढ लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

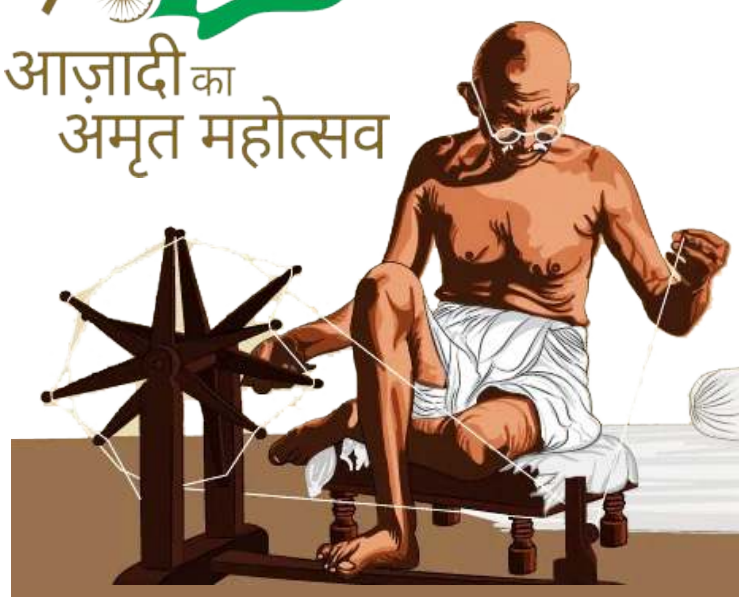

जब गांधी को सौंप दिए थे गहने-जेवर

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूरा देश राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। आजादी की चाह में लोग तप रहे थे। न उन्हें गरीबी का ख्याल था और न किसी अन्य अभाव का। एक ही धुन थी-आजादी। आजादी के आंदोलन की हवा देश के हर शहर, कस्बे, गांव, गली-चबूतरा व पौलियों तक पहुंच चुकी थी। ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां विदेशी आक्रांताओं से निपटने के लिए माहौल तैयार न किया गया हो। इन सबका जिक्र हरियाणवी लोकगीतों में भी मिलता है।

आंदोलन के चलते महात्मा गांधी पूरे देश के नायक बन चुके थे। उनके त्याग व मेहनत से पूरा देश प्रभावित था। वे 1920 में पहली बार भिवानी आए थे। 22 से 24 अक्टूबर, भिवानी में अंबाला डिविजन की पालिटिकल कान्फ्रेंस थी। 22 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी रेलवे स्टेशन पर उतरे तो उन्हें 31 तोपों की सलामी दी गई थी। इसके बाद उन्हें फूल मालाओं से सुसज्जित वाहन में बैठा कर शहर का दौरा कराया गया था। गांधी के साथ शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं के अलावा मौलाना आजाद, स्वामी सत्यदेव, कस्तूरबा गांधी आदि शामिल हुए थे।

गांधी जी दूसरी बार 1921 में भिवानी आए। उस वक्त वे तिलक स्वराज फंड के लिए सहयोग मांग रहे थे। महात्मा गांधी ने यहां 15-16 फरवरी को हरियाणा रूरल कान्फ्रेंस को संबोधित किया था। यह पहली ऐसी कान्फ्रेंस थी जिसमें 30 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया था। इसमें 10 हजार से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई थीं। लोगों में कान्फ्रेंस को लेकर उत्साह इस कदर था कि विभिन्न गांवों और शहरों से हजारों लोग 14 फरवरी की रात को ही भिवानी पहुंच गए थे।

गांधी जी जब तिलक स्वराज फंड के लिए सहयोग एकत्र कर रहे थे तो यहां की महिलाओं ने अपने गहने उतार कर उन्हें भेंट कर दिए थे। डा. मदन मोहन जुनेजा द्वारा लिखित पुस्तक 'हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा' में यह जानकारी दी गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा विस्तार

स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा की तस्वीर बदली है। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया है। पिछले आठ वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में जिस शिद्दत से कार्य हुए हैं वे अपने आप में उल्लेखनीय हैं। इसका उदाहरण वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान देखने को मिला था जब स्वयं मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक नियंत्रण, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ की बदौलत महामारी पर नियंत्रण पाया गया था।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज व स्कूल इत्यादि की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज थे और एमबीबीएस सीटें केवल 700 थी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 6 कॉलेज खोले गए, जिससे एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 1,735 हो गई है।

प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर ज़रूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले इसी ध्येय के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे अथक प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में क्रिटिकल केयर आईसीयू की स्थापना के लिए हरियाणा सरकार को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार-2021 से समानित किया गया है।

स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। जिला करनाल के कुटेल में पंडित दीन दयाल उपाध्याय युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस स्थापित की जा रही है, जो जल्द ही बनकर तैयार होगी। इस युनिवर्सिटी में 750 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और अनुसंधान विभाग भी होंगे।

इसी प्रकार, प्रदेश में नौ मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं। जिसमें, भिवानी में पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज, जींद में राजकीय मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद के छायंसा में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज, नारनौल के कोरियावास में गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कैथल, सिरसा व यमुनानगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज, गुरुग्राम में गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा करनाल में कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज चरण-2 शामिल है। इसके अलावा, रेवाड़ी में एम्स भी बनाया जा रहा है, जो हरियाणा की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में छह नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा हुई थी। इन पर लगभग 194 करोड़ रुपए की लागत आएगी। घोषणा के अनुरूप इन सभी जिलों में बनाये जा रहे कॉलेज का कार्य 85 से 88 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। इसके अलावा, जींद के सफीदों में नर्सिंग कॉलेज के भवन के निर्माण के लिए भूमि खरीदने सहित अन्य प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

राज्य सरकार प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा अधिक से अधिक गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मुहैया करवाने के लिए बीपीएल परिवारों की वार्षिक आमदनी सीमा को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए किया गया है। **-मनोज प्रभाकर**

संपादकीय

मुख्यमंत्री की पारदर्शी सोच

अन्त्योदय से लेकर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, पारदर्शिता हमारी वर्तमान राज्य सरकार का मूलमंत्र बन चुका है। पारदर्शिता की इस मुहिम को मुख्यमंत्री स्वयं गति दे रहे हैं और इसके लिए अब जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

हाल ही में आरम्भ किए गए नए अभियान के तहत तीन जिलों करनाल, रोहतक व सिरसा में मुख्यमंत्री जनसंवाद कायक्रमों का आयोजन हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने 25 दिसंबर को प्रदेश में सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरूआत की थी। सुशासन दिवस लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रदेश में एक पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता था। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं और योजनाओं का सरल तरीके से हर जरुरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना था और आज 40 से अधिक विभागों की 500 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से इनकी जानकारी ले सकता है।

इन जिलों में मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी जनसंवाद कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं और मौके पर ही जन शिकायतों का समाधान करते हैं। सिरसा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने साढ़े तीन घंटे से अधिक समय में लोगों की शिकायतों को सुना तो वहीं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, बीपीएल राशन कार्ड, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित शिकायतें उच्चाधिकारियों ने सुनी।

कार्यक्रम में एक महिला शिकायतकर्ता अपना नाम वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना से काटे जाने की शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के सम्मुख पेश हुई। पहचान पत्र के आंकड़ों से मिलान किया तो शिकायकर्ता के नाम 9 एकड़ जमीन मिली। नियमानुसार अधिकतम दो हेक्टेयर या पांच हेक्टेयर तक की जमीन वालों को ही वृद्धावस्था सम्मान योजना का लाभ मिलता है। महिला शिकायकर्ता द्वारा उसका नाम लाभार्थियों की सूची में डालने के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप तो नौ एकड़ जमीन की मालिकन हो, आपको पेंशन नहीं मिल सकती। महिला ने जब मुख्यमंत्री को अपनी तीन बेटियां होने के बारे में बताया तो मुख्यमंत्री ने महिला को तत्काल अपने ऐच्छिक कोटे से एक लाख रुपए सहायता देने की घोषणा कर दी।

यह घटना जहां एक ओर मुख्यमंत्री की पारदर्शी सोच की प्रतीक है वहीं सरकार का मानवीय चेहरा भी उजागर करती है।

-डॉ. चन्द्र त्रिखा

सतत और समावेशी हरियाणा

हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिला स्तर पर इंडेक्स तैयार की है। इसमें सभी जिलों की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर आकलन किया जा रहा है। इसके साथ ही अलग-अलग हैड बनाकर बजट का प्रावधान किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य 2030 के इंडेक्स में हरियाणा 57 से बढ़कर 67 प्रतिशत तक पहुंच गया है तथा रैंकिंग में भी आगे बढ़ रहा है।

सतत विकास लक्ष्य हरियाणा-2030 को हासिल करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव के स्तर पर समूहों में कार्य किया जा रहा है। गरीबी, स्वास्थ्य, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, लैगिंग समानता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, असमानता कम करना, सतत शहर एवं समुदाय, सतत उत्पाद एवं खपत, पर्यावरण कार्य, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय एवं मजबूत संस्थान सहित 17 मुख्य बिन्दुओं पर कार्य किया जा रहा हैं।

गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र से प्राप्त डाटा अनुसार 5 आयु ग्रुप में बांटकर प्रारम्भिक शिक्षा को शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए बेहतर योजना तैयार की गई है। जन्म से 5 वर्ष आयु ग्रुप में स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए हर बच्चे तक पहुंच बनाई जा रही है। यदि कोई बच्चा स्कूली शिक्षा से बाहर रह गया है तो उनके अभिभावक से तालमेल कर उसे शिक्षित करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा वाणिज्य एवं उद्योग में इज आफ डूईंग बिजनेस में अव्वल रहे हैं तथा पर्यावरण के क्षेत्र में और सुधार करने के लिए बेहतर कार्य किया जा रहा है।

सतत विकास लक्ष्य हरियाणा 2030 एवं सतत और समावेशी हरियाणा 2047 को लेकर विस्तृत प्रस्तुति में अवगत करवाया गया कि अब तक प्रदेश में विभागों ने क्या प्राप्त कर लिया है और विजन 2047 अनुसार क्या प्राप्त करना है तथा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता है।

विभाग कार्यों की रिपोर्ट नियमित भेजें: सीएम

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नीति आयोग के निर्देशानुसार सभी विभाग रैंकिंग में सुधार करने के लिए पैरामिटर अनुसार कार्य करें ताकि सतत विकास लक्ष्य हरियाणा 2030 को हासिल कर सतत और समावेशी हरियाणा 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। उन्होंने कहा कि जो विभाग सतत विकास लक्ष्य हरियाणा 2030 की रैंकिंग एवं पैरामीटर में कमजोर हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए और बिन्दुवार कार्य करें। सभी उपायुक्तों के साथ हर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की भी तैनाती की जाए जो हर माह बैठकें आयोजित कर सतत विकास के लक्ष्य को लेकर समीक्षा करें और उसकी रिपोर्ट तय समय में सरकार को भेजी जाए।

-संवाद ब्यूरो

छत के बिना न रहे कोई परिवार

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में कोई भी व्यक्ति बिना घर के नहीं रहना चाहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति के सिर पर छत मुहैया करवाना उनकी सरकार का प्रमुख उद्देश्य है।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तृत जानकारी लेने के बाद अधिकारियों को कहा कि जिनके पास न घर है, न जमीन है, ऐसे लोगों को छत मुहैया करवाने में वरियता दी जाए। उन्होंने कहा कि मुझे इन गरीब लोगों की चिंता है, इन सभी को घर देने के लिए कोई प्लान बनाओ और पैसे की वजह से घर बनाने का काम नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने अधिकारी मासिक लक्ष्य निर्धारित करें और उक्त योजना के तहत सौ फीसद सर्वे का कार्य जल्द से जल्द पूरा करें।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शहरी व ग्रामीण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना,अटल पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, डायरेक्ट बैनीफिट ट्रांसफर योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति,वन-डिस्ट्रिक्ट वन-प्रोडक्ट योजना के अलावा अमृत सरोवर योजना की भी समीक्षा की और आवश्यकता अनुसार कदम उठाने के निर्देश दिए।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

परिवार पहचान पत्र से लिंक होगी आयुष्मान योजना

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जारी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र से लिंक करने के कार्य को तीव्रता से आगे बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं के लिए 1.80 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा तय की गई है।

आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के सामाजिक, आर्थिक आंकड़ों के आधार पर लाभार्थियों की संख्या 15.50 लाख परिवार है। हरियाणा सरकार के पास नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा पीपीपी में पंजीकृत 25.85 लाख परिवारों का सत्यापित डाटा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकार का 60:40 अनुपात का खर्च वहन की भागीदारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान कार्ड पर राज्य सरकार को अपना लोगो लगाने की अनुमति प्रदान की है। इस बात की जानकारी दी गई कि आयुष्मान अस्पताल ने 519 प्राइवेट व 174 नागरिक अस्पतालों को शामिल किया है। इसी प्रकार 28,78,429 कार्ड जारी किये जा चुके हैं तथा 9,33,489 आयुष्मान परिवारों की पहचान की गई है और लगभग 539 करोड़ रुपए की राशि का क्लेम अब तक दिया जा चुका है। आयुष्मान योजना के प्रीमियम के रूप में 186 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा आयुष्मान योजना में आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, विमुक्त घुमन्तु जाति, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में शामिल लाभार्थियों, भवन निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों, चौकीदार, लंबरदार, आजाद हिंद फ़ौज के सैनिकों के आश्रितों, द्वितीय विश्वयुद्ध सैनिकों के आश्रितों, इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद रहे परिवारों को, हिंदी आंदोलन, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को शामिल करना प्रस्तावित है। इसके अलावा, दिव्यांगों को भी 3 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा आयुष्मान भारत योजना के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विशेष शिविर लगाकर कार्ड वितरण के कार्य में तेजी लाए जाए।

आधार कार्ड व पीपीपी बना महत्वपूर्ण दस्तावेज

केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर उभरे हैं। इतना ही नहीं, इससे पात्र व अपात्र लाभार्थियों की पहचान होने से सिस्टम में पारदर्शिता आई है।

देश में 134 करोड़ लोगों को एक आधार सिस्टम से जोड़ा गया, यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार का डाटाबेस सिस्टम शायद ही किसी अन्य देश के पास उपलब्ध होगा। 'आधार' आज एक अहम दस्तावेज बन गया है, हालांकि बदलते तकनीकी युग में इस सिस्टम में आज बायोमैट्रिक के साथ - साथ फेस रिकॉगनिशन और वॉयस रिकॉगनिशन भी शुरू करने की आवश्यकता है। 'आधार' उपयोग को सरल बनाने और इसके उपयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलों के विषय पर आयोजित हरियाणा राज्य कार्यशाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार ने परिवार की पहचान के लिए भी नई पहल की। इसके तहत, परिवार पहचान पत्र (मेरा परिवार-मेरी पहचान) की शुरुआत हुई। योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए विभागों ने जमीनीस्तर तक अथक प्रयास कर डाटाबेस एकत्र किया। इसके लिए इन-हाउस टीमें बनाई गई। लगभग 4 साल की मेहनत के बाद आज पीपीपी पोर्टल पर लगभग 70 लाख परिवारों और 2.60 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण किया गया है।

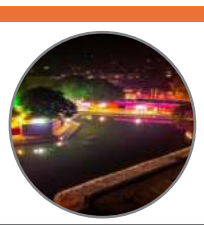

कुरुक्षेत्र के पवित्र तीर्थ ज्योतिसर में भगवान श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप की मूर्ति का अनावरण किया जा चुका है। अब जल्द ही यहां श्री-डी प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी देखने को मिलेगा।

फरीदाबाद के सूरजकुंड में एक अतिरिक्त मेला लगाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय से बातचीत की है।

विदेशी निवेश से खुल रहे प्रगति के नए द्वार

प्रदेश को एमएसएमई के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान

संगीता शर्मा

किसी भी देश व राज्य का विकास औद्योगिक क्रांति पर निर्भर करता है। जिस राज्य में उद्योगों व औद्योगिक आधारभूत ढांचे को अहमियत दी जाती है वह विकास की बुलंदियों में नए आयाम स्थापित करता है। इस सोच को हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा अमल में लाया जा रहा है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देती नीतियां, बुनियादी ढांचा, प्रोत्साहन व सुविधाएं प्रदान की जा रही है। यही कारण है कि हरियाणा में देशी व विदेशी निवेश दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में 40,000 करोड़ का निवेश हुआ है। राज्य में लगातार एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट दोगुना करना है। हरियाणा को एमएसएमई के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल हुआ है, वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी 'स्टेट इज ऑफ डूईंग बिजनेस' के पांचवें संस्करण में हरियाणा को टॉप अचीवर्स कैटेगरी में आ गया है।

औद्योगिक प्लाटों के लिए विशेष लीजिंग पालिॅसी

आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए 29 दिसंबर 2020 को ''हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति, 2020'' लागू की गई। उद्योगों की ''कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस'' को कम करने के लिए औद्योगिक प्लाटों के लिए विशेष लीजिंग पालिॅसी बनाई। वेयरहाऊस और लॉजिस्टिक्स, टैक्सटाइल, फार्मास्युटिकल्स और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय नीतियां पेश की गई। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात बढ़कर 1,74,572 करोड़ रुपए हुआ। इसमें मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट शामिल हैं।

बड़े निवेश आकर्षित हुए

प्रदेश में युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाई की दृष्टि से बड़े-बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं। राज्य में अक्तूबर, 2019 से 31 मार्च, 2022 के दौरान 1,672.43 करोड़ रुपए के निवेश से दस बड़े उद्योग लगे तथा इनमें 4,397 लोगों को रोज़गार मिला। फ्लिपकार्ट समूह मानेसर के पातली हाजीपुर में 140 एकड़ जमीन पर 3 मिलियन वर्ग फीट के कवर क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित कर रहा है। एनरिक एग्रो, पैनासोनिक इंडिया, कंधारी बेवरेजेज, आरती ग्रीन टेक आदि जैसे कई बड़े टिकट निवेश आकर्षित हुए। पानीपत में, ग्रासिम इंडस्ट्रीज अपनी पेंट निर्माण सुविधा में 1,140 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पानीपत में आगामी इंटीग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क में विभिन्न नए व्यवसायों की परिकल्पना की गई है। एकल खिड़की के माध्यम से नए निवेश के समाशोधन के लिए लिया गया और औसत समय 24 दिन था।

पिछले कुछ समय में हरियाणा न केवल निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल के रूप में उभरा है, बल्कि राज्य के प्रति निवेशकों का विश्वास लगातार मज़बूत हुआ है। कोविड महामारी के बावजूद अनेक बड़ी कंपनियों ने हरियाणा में निवेश किया और अब मारुति सुज़ूकी ने अपना प्लांट लगाया है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हरियाणा वर्ष 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को आगे बढ़ाए।

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

हजारों लोगों को रोज़गार

सोनीपत में, मारुति सुजुकी ने 18,000 करोड़ रुपए के निवेश की मात्रा के साथ आईएमटी खरखौदा में 800 एकड़ भूमि पर एक अल्ट्रा मेगा ऑटो उद्योग परियोजना स्थापित कर रही है। यह एक ऐसा कदम है, जिसके माध्यम से 21वीं सदी का भारत 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना से हरियाणा में औद्योगिक क्रांति के अगले दौर का शुभारंभ होगा। इस प्लांट से करीब 11 हजार से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

यदि युवा वर्ग सरकारी व निजी क्षेत्र में नौकरी से वंचित हो जाता है तो ऐसे में व्यक्ति को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वह सूक्ष्म व लघु व मध्यम उद्योग शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सरकार द्वारा इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रियायतें दी जा रही है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 'एम.एस.एम.ई. विभाग' गठित किया गया और इसके लिए सरकार को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए नवाज़ा भी गया है। आर्थिक विकास और आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने तथा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ''हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति, 2020'' लागू की गई।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान हरियाणा का निर्यात 36,390 करोड़ रुपए (व्यापारिक निर्यात सहित) रहा। प्रदेश में लगभग 1,59,622 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित हुए। जिनमें 18,422 करोड़ रुपए का निवेश हुआ तथा 12. 60 लाख लोगों को रोज़गार उपलब्ध हुआ। उद्यमों में लगे कर्मियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल पर 44,672 उद्योग पंजीकृत किया गया।

राज्य सरकार हरियाणा को एक प्रतिस्पर्धी और पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना चाहती है। प्रदेश सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय विकास करना, निर्यात विविधिकरण को बढ़ावा देना और बाहरी निवेश को आकर्षित करके युवाओं के लिए रोज़गार पैदा करना है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से जुड़ी योजनाओं एवं नीतियों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जा रहा है।

- दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री

हरियाणा को बड़ी सौगातें

» वेस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे, कुण्डली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेस-वे, बल्लबगढ़-मुजेसर, मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम-सिकंदरपुर, फरीदाबाद-बल्लबगढ़ मैट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटिड रेलवे ट्रैक, रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन और झज्जर स्थित एम्स के परिसर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जैसी परियोजनाएं। इनके अलावा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के रूप में भी केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है।

औद्योगिक विकास की भावी योजनाएं

» सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, रोहतक में बनाए जाने वाले मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट के तहत प्रशासनिक भवन, स्टैंडर्ड फैक्टरी डिजाइन शैड और ड्राई वेयरहाउस का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, कोर प्रोसेसिंग बिल्डिंग का कार्य भी 30 सितंबर तक पूर्ण हो जाएगा। मेगा फूड पार्क में 1,500 मीट्रिक टन और 1,000 मीट्रिक टन क्षमता के 2 साईलो बनाए जाने हैं, जिनका निर्माण कार्य 15 अक्तूबर तक पूर्ण हो जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 179 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह राज्य सरकार की महत्वकांक्षी परियोजनाओं है, इसलिए इस परियोजना को तय समय में पूरा करने के लिए विशेष रणनीति बनाई जाए।

» बरवाला के इंडस्ट्रियल एस्टेट में टर्नकी आधारित बुनियादा ढांचा सुविधाओं के विकास परियोजना के तहत सिविल कार्य 80 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है और अक्तूबर माह तक संपूर्ण कार्य पूरा हो जाएगा। साथ ही, इस इंडस्ट्रियल एस्टेट में 111 प्लॉट की नीलामी प्रक्रिया भी अमल में लाई गई है।

» सोहना में 500 एकड़ में बन रहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चिरिंग कलस्टर तथा 1,000 एकड़ में स्थापित किए जा रहे आईएमटी, सोहना में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का कार्य किया जा रहा है। दोनों परियोजनाएं दो वर्षों में पूरा होने का अनुमान है।

» गुरुग्राम में करीब 1 हजार एकड़ जमीन पर विकसित की जाने वाली ग्लोबल सिटी का ईपीसी टेंडर प्रक्रिया पर कार्य चल रहा है। इस सिटी में ग्लोबल सिटी दुबई और सिंगापुर की तरह सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इस ग्लोबल सिटी के बनने से न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं को भी बेहतर रोज़गार मिल सकेगा।

» 'हरियाणा एंटरप्राइजिज एंड एंप्लाइमेंट पॉलिसी 2020' के अंतर्गत 44 योजनाओं में से 37 को ड्रॉफ्ट और नोटिफाई कर दिया है। विभिन्न इन्सेंटिव के लिए 2,156 आवेदन आए हैं। राज्य में आठ मेगा प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल इन्सेंटिव को स्वीकृति दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स में करीब 24,328 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है।

» 'हरियाणा एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2018' के अलावा 'पदमा', 'हरियाणा आत्मनिर्भर टैक्सटाइल पॉलिसी 2022-25', 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना', 'कन्वरजेंश विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम्स' के अलावा एमएसएमई के तहत भी उद्योगों व रोज़गार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

हरियाणा में ग्रुप-सी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नवंबर महीने में होगा। इसके बाद ग्रुप-सी के लिए दूसरे लेवल का टेस्ट आयोजित होगा।

राज्य में ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार ऑनलाइन सुविधा चलाई जा रही है। किसान अपनी फसल इसके माध्यम से केरल से असम तक के व्यापारियों को बेच सकते हैं। जहां उन्हें फसल के अच्छे दाम मिलेंगे।

किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का लक्ष्य

केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए अनेक योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इससे किसानों की लागत कम होगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

प्राकृतिक खेती को लेकर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों और किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति ज़ागरूक करने का प्रयास किया गया।

आचार्य डॉ. देवव्रत ने इस अवसर पर कहा कि प्राकृतिक खेती से धरती की सेहत अच्छी होगी और लोगों को भी अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद मिल पाएंगे। जब लोगों को प्राकृतिक खेती के उत्पाद मिलेंगे तो कैंसर जैसी बीमारियों से भी निजात मिल पाएगी। इसलिए देश के लोगों को स्वस्थ रखने, किसानों की लागत कम करके आय में वृद्धि करने, भूमि की सेहत में सुधार लाने तथा पर्यावरण को

स्वच्छ रखने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को ज़ागरूक करने के साथ-साथ प्रशिक्षित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती को लेकर केंद्र और राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़कर काम कर रही है। इस कार्य को लेकर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में काफी समय से काम किया जा रहा है। यहां पर सरकार के सहयोग से प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा चुका है। इस प्रशिक्षण केंद्र में किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के अंतर को भी बारीकी से समझाया जाता है।

उन्होंने कहा कि आज प्राकृतिक खेती हर प्राणी की आवश्यकता है। इस विषय को ज़हन में रखकर ही प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती से एक एकड़ में 33 क्विंटल फसल की पैदावार ली जा सकती है और प्रथम वर्ष से ही अधिक उपज ली जा सकती है, लेकिन इस तकनीकी को अपनाने के लिए प्रशिक्षण लेने की जरूरत है। इस तकनीक में देसी गाय का अहम योगदान रहेगा।

शुगर मिलों में लगेंगे एथनॉल प्लांट

शुगर मिलों में लगाए जाने वाले एथनोल प्लांट के निर्माण कार्यों में तेज़ी लाई जाएगी ताकि इनके चलने से किसानों को ज़्यादा लाभ मिल सके। इसके अलावा, किसान गन्ने की नई किस्म 15023 की अधिक से अधिक पैदावार करें। इस किस्म पर किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

शाहबाद शुगर मिल में 60 केएलपीडी क्षमता का एथनॉल प्लांट स्थापित किया जा चुका है और पानीपत शुगर मिल में 90 केएलपीडी क्षमता का एथनॉल प्लांट शीघ्र ही लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त रोहतक, करनाल, सोनीपत, जीन्द, कैथल, महम, गोहाना व पलवल शुगर मिलों में एथनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं।

देश में किसानों को सबसे ज़्यादा गन्ने का दाम देने वाला हरियाणा प्रदेश है। किसानों की भलाई को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही गन्ने के भाव तय किए जाएंगे। किसानों के गन्ने की बकाया राशि का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। केवल एक शुगर मिल का शेष है, उस शुगर मिल के किसानों की बकाया राशि का भुगतान भी जल्द ही करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के लिए गन्ने की नई किस्म 15023 तैयार की गई है। इस किस्म को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को भी जल्द ही इस किस्म के सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस किस्म का ज़्यादा से ज़्यादा बीज तैयार किया जाए ताकि किसान इसका अधिक उत्पादन कर ज़्यादा लाभ उठा सकें। इस किस्म को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। गत वर्ष इस नई किस्म की बिजाई करने वाले किसानों को भी सत्यापन करके वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

गन्ने की नई किस्मों होंगी तैयार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सहकारी शुगर मिलों एवं प्राइवेट शुगर मिलों के उत्पादन में जो अंतर है, इसे दूर करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी ज़ल्द ही रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर शुगर मिलों की जवाबदेही तय की जाएगी। गन्ने की नई किस्मों को तैयार करने के लिए गन्ना प्रजनन संस्थान करनाल को 50 एकड़ भूमि देने के लिए भूमि का चयन करने के भी निर्देश दिए ताकि प्रदेश के किसानों को नई नई किस्मों के बीज उपलब्ध करवाए जा सकें। इसके अलावा पुरानी गुड़-खाण्डसारी ईकाइयों के लाइसेंस नवीनीकरण करने और नई ईकाइयों को लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया। गत वर्ष 168 गुड़ तथा 2 खाण्डसारी ईकाइयों को लाईसेंस जारी किए गए थे।

खरीफ फसलों की खरीद के लिए मंडियां तैयार

खरीफ फसलों की खरीद एक अक्टूबर से की प्रारंभ हो गई। इस दौरान मूंग, मूंगफली, अरहर, उड़द और तिल की खरीद होगी। फसलों की खरीद के लिए प्रदेश में 100 से अधिक मंडियों की व्यवस्था की गई है।

फसलों की समयबद्ध तरीके से खरीद, उसकी स्टोरेज तथा मंडियों में गनी बैग्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ताकि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की समस्या न आए।

विपणन सत्र 2022-23 के दौरान मूंग की खरीद शुरू हो गई, यह 15 नवंबर तक जारी रहेगी। मूंगफली, अरहर, उड़द और तिल की खरीद 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। खरीफ फसलों की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर होगी। हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हैफेड के अलावा नैफेड द्वारा खरीफ फसलों की खरीद की जाएगी।

खरीफ फसलों की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में मंडियों की व्यवस्था की गई है। मूंग की खरीद के लिए 16 जिलों में 38 मंडियां, अरहर की खरीद के लिए 18 जिलों में 22 मंडियां, उड़द की खरीद के लिए 7 जिलों में 10 मंडियां, मूंगफली की खरीद के लिए 3 जिलों में 7 मंडियां तथा तिल की खरीद के लिए 21 जिलों में 27 मंडियां खोली गई हैं।

गया कि इस वर्ष मूंग की 41,850 मीट्रिक टन उत्पादन की संभावना है। इसी प्रकार अरहर की 1044 मीट्रिक टन, उड़द का 364 मीट्रिक टन, तिल का 425 मीट्रिक टन तथा मूंगफली का 10,011 मीट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है।

बाजरा की एमएसपी पर खरीद होगी

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले बाजरा के लिए सरकार एक लाख 60 हजार मीट्रिक टन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। बिजाई के रकबे को देखते हुए शेष उपज के लिए किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ दिया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने नारी शक्ति पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अवार्ड्स.जीओवी.इन पोर्टल पर 31 अक्तूबर तक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होगा। इस वर्ष जयंती का मुख्य महापर्व 4 दिसंबर को है। इस दौरान 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

खारे पानी में झींगा उत्पादन

सिरसा में मछली पालकों के लिए स्थापित की जाएगी टेस्टिंग लैब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए नई-नई योजनाएं व प्रकल्प बना रहे हैं। उसमें से एक मछलीपालन है। साधारण किसान फसल से ज़्यादा आमदनी हासिल नहीं कर सकता, लेकिन पशुपालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन आदि से अच्छी आमदनी ले सकता है। इसी मकसद से हरियाणा सरकार द्वारा मछलीपालन से संबंधित नई-नई घोषणाएं की जा रही है, जिससे मछलीपालकों को अधिक मुनाफ़ा मिल सकें। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा के चोरमार खेड़ा गांव में आयोजित झींगा किसानों की कार्यशाला में मत्स्य पालक किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' के तहत केंद्र सरकार से आने वाली सब्सिडी में अगर देरी होती है तो वह सब्सिडी हरियाणा सरकार एडवांस में देगी।

थोक मछली मार्केट होगी स्थापित

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मछली की खरीद व बिक्री के लिए झज्जर या गुरुग्राम में से किसी एक जिले में थोक मछली मार्केट स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को आर्थिक तरक्की में लाभ मिलेगा। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की तरह मछली पालन किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इसी प्रकार मछली पालन में बीमा करने के लिए भी सरकार बैंक व बीमा कंपनियों से बातचीत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मछली पालन में बिजली खपत एक बड़ा विषय है। फिलहाल सरकार जिन किसानों की खपत 20 किलोवाट है, उन्हें 4.75 प्रति यूनिट दर पर बिजली उपलब्ध करवा रही है। मछली पालक अपने प्लॉट पर सोलर प्लॉट भी लगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रति हार्स पावर 20 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। जो अधिकतम दो लाख रुपए तक हो सकती है।

भिवानी में बनेगा एक्वापॉर्क

भिवानी के गरवा गांव में 30 करोड़ की लागत से एक्वापार्क बनाया जाएगा। यह एक्वापार्क 25 एकड़ में होगा। इसमें मछली पालन से जुड़े नए-नए शोध, मछली पालन की नई किस्म, बीज पर शोध किया जाएगा। इससे मछली पालकों को सीधे लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' से मिलने वाला लाभ अगले तीन वर्ष तक मिलेगा। झींगा बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। इससे विदेशी मुद्रा देश में आती है जो भारत की आर्थिक तरक्की के लिए महत्त्वपूर्ण है।

सिरसा ने देश में क्रांति लाने का काम किया

कृषि एवं मत्स्य पालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि सिरसा के किसान बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने खारे पानी में झींगा उत्पादन कर देश में नई क्रांति लाने का काम किया है। यहां के किसानों ने अन्य किसानों को भी रास्ता दिखाया है कि कैसे खारे पानी को निकालकर मछली पालन किया जा सकता है। प्रदेश में 10 लाख एकड़ जमीन में खारे पानी की समस्या है। प्रदेश के सभी किसान इस तरह लागत लगाकर झींगा उत्पादन का जोखिम नहीं ले सकते लेकिन 400 किसानों ने अब कामयाबी की कहानी लिखी है। दलाल ने कहा कि ऐसा कोई कारोबार नहीं है, जिसमें पूंजी लगाकर छह महीने में मुनाफ़ा लिया जा सकता हो लेकिन झींगा उत्पादन ऐसा काम है, जिसमें छह महीने में पूंजी व लागत पूरी हो जाती है और अगले छह महीने में मुनाफ़ा ले सकते हैं।

दलाल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि मछली पालकों के लिए हैदराबाद से बीज की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मत्स्य विभाग को मज़बूत किया जाए और मछली पालकों के लिए जांच लैब खोली जाए। इसके अतिरिक्त प्रोसेसिंग प्लॉट लगाने के लिए स्कीम बनाई जाए। उन्होंने किसानों को सहकारी बैंकों से मछली पालन व झींगा उत्पादन के लिए ऋण उपलब्ध करवाने की अपील भी की। प्रदेश के 10 हजार किसानों को झींगा मछली पालन करके करोड़पति बनाने का लक्ष्य लिया है।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के मिठड़ी गांव में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की लाभार्थी वीरपाल कौर के झींगा उत्पादन प्लॉट का अवलोकन किया।

झींगा उत्पादन को 4 हजार मीट्रिक टन करने का लक्ष्य

- हरियाणा में निरंतर सेम व खारे पानी वाली जमीन में झींगा उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं।
- वर्ष 2014-15 में झींगा पालन का क्षेत्र 70 एकड़ था और कुल उत्पादन 140 मीट्रिक टन था जो 2021-22 में बढ़कर 1250 एकड़ व 2900 मीट्रिक टन हो गया है।
- सरकार ने इस वर्ष का लक्ष्य 1,250 एकड़ से बढ़ाकर 2,500 एकड़ करने तथा उत्पादन 2,900 मीट्रिक टन से चार हजार मीट्रिक टन रखा है।
- हरियाणा में वर्ष 2014 में कुल 43 हजार एकड़ में 1 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन होता था और इस वर्ष यह लक्ष्य बढ़ाकर 54 हजार एकड़ और 2 लाख 10 हजार मीट्रिक टन रखा गया है।
- प्रदेश में 25 लाख मत्स्य बीज उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

फसल अवशेष के समुचित प्रबंधन की तैयारी

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर पूर्ण रूप से रोक लगाने तथा पराली का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु नीतिगत फ्रेमवर्क बनाया है। इसके लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा हरियाणा एक्स-सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

हरियाणा एक्स-सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी - 2022 का उद्देश्य पराली आधारित बायोमास, बिजली परियोजनाओं, उद्योगों, कम्प्रैस्ड बायोगैस संयंत्रों, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों, ईंट-भट्ठों, पैकेजिंग सामग्री इत्यादि में निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। इतना ही नहीं, किसानों को अपने खेत में पराली को काटने, गठरी बनाने और स्टोर करने हेतु प्रोत्साहित करना और विभिन्न परियोजनाओं में उपयोग हेतु इसे बेचने के लिए सुविधा प्रदान करना है।

इस नीति के माध्यम से फसल के अवशेषों की मांग और आपूर्ति प्रबंधन के लिए किसानों व उद्योगों/गौशालाओं/उपयोगकर्ताओं के बीच लिंक स्थापपित किया जाएगा। साथ ही, विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों, ईंट भट्टों या किसी अन्य औद्योगिक, वाणिज्यिक या संस्थागत प्रतिष्ठानों में पराली का उपयोग करने पर भी जोर दिया जाएगा। नई प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देना भी इस नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि पराली के उपयोग तथा बायोमास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई जाएंगी। राज्य में पॉवर प्रोजेक्टस, सीबीजी प्लांट, एथनोल और अन्य बायोफ्यूल के उपयोग को प्रचलित करने के लिए इस नीति के प्रारूप में विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों का भी प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि पराली की मांग के लिए जिलावार मैपिंग करने की रणनीति को भी नीति में शामिल किया गया है।

फसल अवशेष प्रबंधन

कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक व प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी के तहत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर तथा कस्टमर हायरिंग सेंटर खोलने के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी पर बेलिंग यूनिट (हे-रेक, शर्ब मास्टर और स्ट्रॉ बेलर) उपलब्धत करवाई जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सब्सिडी पर 600 बेलिंग यूनिट प्रदान की जा रही है। इनमें से 290 बेलिंग यूनिट पानीपत के बाहोली में स्था2पित 2जी एथनोल प्लांट के लिए चिह्नित कल्स्टसर में आवंटित की गई हैं।

हरियाणा सरकार के हैफेड को सऊदी अरब में 20,000 मीट्रिक टन चावल के निर्यात का ऑर्डर मिला है। जिसकी कीमत 21.95 मिलियन अमरीकी डालर होगी।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत बायोगैस प्लांट योजना शुरू की गई है। योजना के तहत बायोगैस प्लांट की लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

यमुनानगर जनपद का हिन्दी साहित्य

शिवालिक श्रृंखलाओं की तलहटी में यमुना नदी के तट पर बसा यमुनानगर जनपद युगीन परिस्थितियां, क्षेत्रीय विरासत एवं अंचल विशेष की इबारत लिखता जनजीवन अपने आंचल में बेशुमार रतन समेटे है। ऐसे ही रतनों में से एक बड़े साहित्यकार साहिब सिंह मृगेंद्र। मृगेंद्र को रीतिकालीन संध्या का महान कवि माना गया है। इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की, जिसमें से 20 ग्रन्थ उपलब्ध हैं। इन रचनाओं की विषय नीति, इतिहास, पशु विज्ञान, अध्यात्म, योग, श्रृंगार तथा व्याकरण । हरियाणवी शैली की प्रगाढ़ रंगत साहिब सिंह मृगेन्द्रं को इस अंचल के विशेष रचनाकार का प्रतिष्ठित करती है।

ओम कुकरेती यमुनानगर के विलक्षण रचनाकार है। उनके उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, कविता, व्यंग्य लेख, फ़ीचर और सामयिक आलेखों में उनकी कलम प्रभावशाली रचना कर्म निभाती है। भारतीय वायुसेना से अध्यापन फिर पत्रकारिता करते इनके चार उपन्यास, तीन कहानी संग्रह, दो निबन्ध संग्रह तथा शिकार कथा-संग्रह प्रकाशित हुए हैं।

महाकवि सूर सम्मान से अलंकृत डॉ.कंवल नयन कपूर यमुनानगर के लब्धप्रतिष्ठित रचनाकार हैं। सांस्कृतिक मूल्यों की चिंता उनकी काव्य चेतना का सशक्त आधार है । डॉ कपूर एक श्रेष्ठ रंगकर्मी हैं। श्रीमद्भागवत गीता का काव्य रूपांतरण 'इदम शरीरम' के लिए सन् 1995 में इन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा द्वारा राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया ।

सचिन्द्र रश्मि गर्ग 1960-70 दशक के कवि हैं । उनकी एकमात्र काव्य कृति 'विहान' है। उनकी कविताओं में ग्राम्य जीवन, संस्कृति के स्वर, राष्ट्रप्रेम, बाल मनोविज्ञान एवं पारिवारिक परिवेश के साथ - साथ मानवीय संवेदनाओं से उनका जुड़ाव आज भी प्रासंगिक लगता है।

डॉ. बी. मदन मोहन की पहचान कवि, आलोचक, बाल साहित्यकार एवं यात्रा-वृत्तान्तकार के रूप में है। तीन काव्य संग्रह, तीन बाल काव्य संग्रह, एक गीत काव्य संग्रह तथा एक यात्रा वृत्तान्त में देश, समाज अपनी समग्रता में उभरा है।

कथाकार ब्रह्मदत्त शर्मा ने विगत एक दशक में हरियाणा के कथाकारों में ख्यातिपूर्ण स्थान अर्जित किया है। अब तक उनके तीन कहानी-संग्रह तथा एक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी कहानियों के पात्र इतने जीवंत हैं कि पाठक को वे सब अपने जीवन के आस-पास दिखाई देते हैं। उत्तराखंड त्रासदी पर लिखा इनका उपन्यास 'ठहरे हुए पलों में' जहां एक साथ यात्रा संस्मरण, फ़ीचर एवं कथा-किस्से का बोध कराता है।

यमुनानगर जनपद के दो ऊर्जावान साहित्यिक डॉ अनिल 'सवेरा' और डॉक्टर संजीव कुमार असमय ही काल का ग्रास बन गए। जिस सक्रियता और गंभीरता से उनकी सृजन यात्रा चल रही थी उनसे बड़ी अपेक्षाएं थीं। हरियाणवी लोक साहित्य तथा लोक परंपराओं पर शोध, आलोचना, समीक्षा, लघु कथा, निबंध, बाल-गीत, फीचर लेखन के साथ-साथ वे लोक संस्कृति के गंभीर अध्येता थे।'हरियाणवी लोक नाट्यकार एवं सांगी', 'हरियाणवी लोक-संस्कृति', 'हरियाणा की लोक कथाएं' तथा 'हरियाणवी नृत्य-गीत' उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं।

डॉ संजीव कुमार को प्रतिभावान नाटककार के रूप में हमेशा याद किया जाएगा । संजीव द्वारा रचित नाटकों-एकांकियों का देशभर के मंचों पर दो सौ से अधिक बार मंचन होना उनकी लोकप्रियता और श्रेष्ठज नाटककार की पहचान को रेखांकित करता है।

डॉ. बहादुर सिंह हिंदी साहित्येतिहास तथा हरियाणवी एवं राजस्थानी लोक साहित्य के शोधकर्ता हैं। भाषा विज्ञान तथा भारतीय काव्यशास्त्र पर भी उनका गहन अध्ययन है। उनके दस ग्रंथों में 'काव्य भाषा का शैली वैज्ञानिक विश्लेषण', 'हिंदी साहित्य का इतिहास' तथा 'बटेऊ की खाट' प्रमुख हैं।

'अमर' अम्बालवी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में समान अधिकार से लिखने वाले साहित्यकार हैं। अब तक सभी भाषाओं की चार पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। हिंदी में 'रुनझुन' गज़ल संग्रह है। गज़ल के अनुशासन को अत्यधिक कड़ाई से निभाते हुए वह अपने भावों को इस तरह व्यक्त करते हैं कि पाठक उनमें डूब जाता है।

अशोक अग्रवाल निरंतर और प्रभावी लेखन कर रहे हैं। 'प्रतिसंवेदन' इनका प्रथम कविता संग्रह है। उनकी काव्य-सृजना भविष्य की बुनावट का ऐसा कैनवस है जिस पर अभी और आकर्षक काव्य चित्र उभरने बाकी हैं।

कथाकार और कवि बलदेव राज भारतीय की दो कृतियाँ- 'निमंत्रण पत्र' (कथा-संग्रह) एवं 'अधूरी कविता' (काव्य संग्रह) प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका साहित्यिक परिवारिक, सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यबोध, राष्ट्रप्रेम तथा मानवीय मन के संवेगों को इस अंदाज में प्रस्तुत करता है कि पाठक को अपने जीवन की वास्तविकता के करीब लगता है।

मीर अवार्ड से सम्मानित डॉ दीप बिलासपुरी की गज़लें हिंदी तथा उर्दू में लिखी, गाई और सराही गई हैं। इनके अब तक सात गज़ल संग्रह तथा कई संगीत एल्बम आ चुके हैं। चार हजार अशआर से सुसज्जित एक ही गज़ल का संग्रह 'शाहकार' इनकी साहित्यिक प्रतिभा का परिचायक है।

मदन 'शेखपुरी' की साहित्य यात्रा कविता, लघुकथा, लघु नाटिका, रागिनी तथा बालगीतों के पड़ाव तय करती निरंतर जारी है। उपर्युक्त विधाओं पर इनकी छह पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। नारी-अस्मिता, समाज-व्यवस्था, देश गौरव तथा नई पीढ़ी को संस्कारों की विरासत सौंपने की पक्षधर इनकी रचनाएँ पाठकों को बहुत दूर तक प्रभावित करती हैं।

डॉ.सुनीता कपूर के दो बाल काव्य-संग्रह प्रकाशित हुए हैं-बाल बोधिनी भाग- एक और दो। गीत शैली में रचित इन रचनाओं को चित्रों के साथ प्रस्तुत किया गया है । बाल मन की उभरती जिज्ञासाओं का उन्होंने सहज सरल किंतु बोधगम्य निरूपण किया है।

अरुण कैहरबा हरियाणा के हिंदी साहित्य को प्रगतिशील नज़रिये से बड़ी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से निभा रहे हैं। कैहरबा ने पिछले कुछ ही वर्षों में आलोचना, समीक्षा, स्तंभ-लेखन एवं सम्पादन के क्षेत्र में विशेष पहचान अंकित की है।

यमुनानगर की साहित्यिक परिधि में प्रेम बजाज निरंतर रचना कर्म करते रहने के बाद भी साहित्यकों की दृष्टि से लगभग ओझल ही रहे । उनकी दो हजार से अधिक मौलिक रचनाएं तथा लेख प्रकाशित हो चुके हैं।

पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हर्ष देव चोपड़ा का शब्द-विन्यास भी गज़ब का है। कविता, गीत, गज़ल तथा हास्य-व्यंग्य पर इनकी प्रभावी पकड़ है। देशभक्ति, समाज की बेहतरी और मानवीय मूल्यों का संरक्षण इनकी रचनाओं का प्रमुख भाव है।

इनके साथ युवा कवि अनिल खारवन, विनय मोहन ,सारूप चौहान, नरेश शाद, रमेश भारती, पंकज शर्मा और तरुण शर्मा, राहुल सैनी, मोहित तेजली, शिवानी शर्मा, पंकज भारद्वाज, संदीप झा और उर्दू के उस्ताद शायर जनाब 'मयकश' अम्बालवी तथा पंजाबी के सशक्त हस्ताक्षर डॉ रमेश कुमार ने कविता, गीत तथा गज़ल में यमुनानगर के साहित्यिक परिवेश को समृद्ध बनाने में इन रचनाकारों ने साहित्य-सम्पदा को समुन्नत किया है।

-डॉ. बी. मदन मोहन

'हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता' योजना

वर्तमान सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में एक 'हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना' को शुरू किया गया है। योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोज़गार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस योजना के तहत निगम द्वारा ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि का अपना काम शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं स्वरोज़गार स्थापित कर सकेंगी एवं दूसरे नागरिकों को भी रोज़गार प्रदान कर सकेंगी। यह योजना देश की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएगी।

आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य

हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लाभार्थियों को 36 महीने के लिए 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा योजना के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

लाभार्थी के लिए शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर ना हो। महिला की पारिवारिक आय 5 लाख या इससे कम होनी चाहिए। आवेदक महिला का नाम परिवार पहचान पत्र में दर्ज होना अनिवार्य है। महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र यदि हो तो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि लगाने होंगे।

हिंदी दिवस पर रचनाकार सम्मानित

हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकूला द्वारा जिन लेखकों को कृति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया उनमें सर्वश्री हरभगवान चावला, सिरसा (इसी आकाश में), विकेश निझावन, अम्बाला शहर (छुअन तथा अन्य कहानियाँ), उषा अग्रवाल, मुम्बई (बर्फ के कालीन पर नन्हें पांव), बलराम सैनी, अम्बाला (ढह गई दीवार), वेदप्रकाश नागपाल, चंडीगढ़ (मेरा ज़िन्दगी नामा), बी.डी. कालिया, पंचकूला (साहित्य प्रपात), लहणा सिंह अत्री, फफड़ाना, करनाल (चल दिखादयूँ अजब नजारा), राममेहर सिंह, जीन्द (हरियाणवी रागिनी साहित्यिक विश्लेषण), सुशील 'हसरत' नरेलवी चण्डीगढ़ (तसव्वुर के आईने से), जगवीर सिंह, भिवानी (धर्म एवं दर्शन), सतीश चन्द्र अग्रवाल, पंचकूला (सुसंस्कार निर्माण (प्रज्ञा प्रसंग), आनन्द प्रकाश आर्टिस्ट, भिवानी ('खोया हुआ विश्वास'), विनोद वर्मा 'दुर्गेश', भिवानी ('लोक साहित्यकार: जयलाल दास'), सूबेसिंह मौर्य, जीरकपुर ('सुन्दरकाण्ड का सौंदर्य एवं मानव हित'), प्रदीप नील, हिसार ('जाट कहवै, सुण जाटणी'), अनिल कुमार पृथ्वीपुत्र, भिवानी ('अमर जवान सतसई'), अजय सिंह राणा, चंडीगढ़ (तेरा नाम इश्क़), जसविंदर शर्मा, पंचकूला (जलती हुई नदी), जितेन्द्र कुमार, चण्डीगढ़ (व्यंग्य बाणों का तूणीर), रिसाल जांगड़ा, कैथल (घुँघरू बचपन के), संतोष गर्ग, पंचकूला (सनातन वार्ता), हरिपाल गौड़, रोहतक (सांग-सुधा), ज्ञानी देवी, करनाल (दरद नै ए दवा बणा), शर्मीला, हिसार (तीन टुकड़ा सूरज), विजय 'विभोर', रोहतक (फिर वही पहली रात), लाजपत राय गर्ग, पंचकूला (पल जो यूँ गुज़रे), पंकज शर्मा, अम्बाला शहर (मुफ्त बातों के मुफ्तलाल), बलजीत सिंह, हिसार (काले पानी का सफेद सच), महेन्द्र सिंह 'सागर', भिवानी (बाल उड़ान), रामबीर सिंह, सोनीपत ('लोककला सिरमौर : निहालचंद शिवचरण') तथा इसके अतिरिक्त 10 कहानी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

हरियाणा की डीबीटी योजना पूरे देश में अव्वल है। इसमें 150 योजनाओं को डीबीटी व आधार से लिंक किया गया है। इन योजनाओं में 94 योजनाएं राज्य की तथा 56 योजनाएं केंद्र सरकार की शामिल हैं।

रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना के अंतर्गत फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने हेतु चयन किया गया है। इस परियोजना की कुल राशि 262 करोड़ रुपए है।

राखीगढ़ी को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान

विशेष प्रतिनिधि

सिंधु घाटी सभ्यता की ऐतिहासिक नगरी राखीगढ़ी, हिसार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा राखीगढ़ी में म्यूजियम का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 हजार वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सहेज कर रखा जाएगा। राखीगढ़ी के पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित होने से पर्यटन बढ़ेगा तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राखीगढ़ी का तीन बार दौरा कर चुके हैं।

राखीगढ़ी में बन रहे इस म्यूजियम में फोटोग्राफ्स लैब्स तैयार की गई है, जिनमें चित्रों के माध्यम से आगंतुक राखीगढ़ी के इतिहास को जान सकेंगे। इसके अलावा, म्यूजियम में किड्ज़ ज़ोन भी बनाया गया है। पहली बार हरियाणा में किसी म्यूजियम में किड्स ज़ोन का निर्माण करवाया गया है ताकि बच्चे भी खेल-खेल में इतिहास से अवगत हो सकें। इसके अलावा, ओपन एयर थिएटर, गैलरी, पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया गया है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा देश में पर्यटन स्थलों व पांच ऐतिहासिक स्थल बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। उनमें राखीगढ़ी भी शामिल है। प्रदेश सरकार भी यहां 32 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक संग्रहालय बना रही है। इसमें रेस्ट हाउस, हॉस्टल और एक कैफे का निर्माण किया जा रहा है। पुनर्वास कार्यों के लिए 8 करोड़ 50 रुपए जारी किए जा चुके हैं। राखीगढ़ी को विश्व स्तरीय पुरातत्व एवं पर्यटन स्थल बनाने में केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है।

ग्रामीणों को होम स्टे नीति के तहत लाइसेंस

हरियाणा सरकार द्वारा होमस्टे नीति तैयार की गई है, जिसके तहत ग्रामीण अपने घरों में एक या दो कमरों का उपयोग टूरिस्ट के ठहराव के लिए कर सकेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से विधिवत लाइसेंस दिए जाएंगे। इस होमस्टे नीति से राखीगढ़ी के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश में होम स्टे कल्चर को प्रचलित करना है, ताकि एक और जहां स्थानीय लोगों को नया रोजगार मिले, वहीं टूरिस्ट को भी हरियाणा की संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिले।

सड़क तंत्र होगा मजबूत

राखीगढ़ी तक हांसी, जींद और बरवाला तीनों तरफ से सड़क तंत्र मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा, गैबीनगर (किनर) से राखीगढ़ी तक लगभग साढे 5 किलोमीटर की सड़क का चौड़ाकरण और सुधारीकरण किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त जमीन ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से जल्द खरीदी जाएगी। राखीगढ़ी के बारे में नेशनल हाईवे और राज्य हाईवे पर साइन बोर्ड लगाई जाएंगे। इसके अलावा, हरियाणा पर्यटन निगम के परिसरों और अन्य पर्यटन स्थानों पर राखीगढ़ी के ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा ताकि प्रदेश व देश के लोगों को राखीगढ़ी के बारे में जानकारी मिल सके और आगामी दिनों में राखीगढ़ी में पर्यटन को बढ़ावा मिले।

राखीगढ़ी का इतिहास

राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार के नारनौंद उपमंडल में स्थित है। यहां राखीखास और राखीशाहपुर गांवों के अलावा आस-पास के खेतों में पुरातात्विक साक्ष्य फैले हुए हैं। राखीगढ़ी में सात टीले (आरजीआर-1 से लेकर आरजीआर-7) हैं। ये मिलकर बस्ती बनाते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इस गांव में पहली बार 1963 में खुदाई शुरू की थी। इसके बाद 1998-2001 के बीच डॉ. अमरेंद्रनाथ के नेतृत्व में एएसआई ने फिर खुदाई शुरू की। बाद में पुणे के डेक्कन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. वसंत शिंदे के नेतृत्व में 2013 से 2016 व 2022 में राखीगढ़ी में उत्खनन कार्य हुआ है।

राखीगढ़ी में 1998 से लेकर अब तक 56 कंकाल मिले हैं। इनमें 36 की खोज प्रो. शिंदे ने की थी। टीला संख्या-7 की खुदाई में मिले दो महिलाओं के कंकाल करीब 7,000 साल पुराने हैं। दोनों कंकालों के हाथ में खोल (शैल) की चूड़ियां, एक तांबे का दर्पण और अर्ध कीमती पत्थरों के मनके भी मिले हैं। खोल की चूड़ियों की मौजूदगी से यह संभावना जताई जा रही है कि राखीगढ़ी के लोगों के दूरदराज के स्थानों के साथ व्यापारिक संबंध थे। प्रो. शिंदे के अनुसार राखीगढ़ी में पाई गई सभ्यता करीब 5000-5500 ई.पू. की है, जबकि मोहनजोदड़ो में पाई गई सभ्यता का समय लगभग 4000 ई.पू. माना जाता है। मोहनजोदड़ो का क्षेत्र करीब 300 हैक्टेयर है, जबकि राखीगढ़ी 550 हैक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में फैला है। प्रो. शिंदे के अनुसार प्राचीन सभ्यता के साक्ष्यों को संजोए राखीगढ़ी में मिले प्रमाण इस ओर भी इशारा करते हैं कि व्यापारिक लेन-देन के मामले में भी यह स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ज़्यादा समृद्ध था।

अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान से इसका व्यापारिक संबंध था। खासतौर पर आभूषण बनाने के लिए लोग यहां से कच्चा माल लाते थे, फिर इनके आभूषण बनाकर इन्हीं जगहों में बेचते थे। इस सभ्यता के लोग तांबा, कार्नेलियन, अगेट, सोने जैसी मूल्यवान धातुओं को पिघलाकर इनसे नक्शीदार मनके की माला बनाते थे। पत्थरों या धातुओं से जेवर बनाने के लिए भट्ठियों का इस्तेमाल होता था। इस तरह की भट्ठियां भारी मात्रा में मिली हैं। यहां मिले कंकालों का डीएनए परीक्षण चल रहा है।

कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में 200 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत पर आधारित एक विश्व स्तरीय डिजिटल म्यूजियम स्थापित करने की योजना है। माना जाता है कि यह विश्व स्तरीय पर्यटन का आकर्षण केंद्र होगा।

राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हेतु बहादुर बच्चों के लिए 15 अक्तूबर, तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयु 6 से 18 वर्ष तक और बहादुरी का कार्य पहली जुलाई, 2021 से 30 सितंबर, 2022 तक का हो।

कनाडा पहुंचा श्रीमद् भगवत गीता का आलोक

कनाडा की राजधानी ओटावा स्थित संसद भवन में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को कनाडा की संसद के पुस्तकालय में सुशोभित किया गया। संसद पुस्तकालय की प्रमुख सुश्री सोन्या ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद और भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य से संसद पुस्तकालय के लिए गीता प्राप्त की।

समारोह में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का संदेश भी पढ़ा गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव महोत्सव के मौके पर पार्लियामेंट हिल में सभी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन कनाडाई लोगों को एक साथ लाते हैं और उन्हें अपनी विविधता का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवद गीता में निहित शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश सार्वभौमिक है।

टोरंटो में गीता यज्ञ

तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के आखिरी दिन कनाडा के टोरंटो में गीता यज्ञ का आयोजन किया गया जिसके पश्चात शहर में एक शोभायात्रा भी निकाली गई। यज्ञ और शोभायात्रा में कनाडा में रह रहे हज़ारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

स्वामी ज्ञानानंद महाराज, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉ. कमल गुप्ता, हरियाणा सार्वजनिक उप‘म ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित कुमार अग्रवाल, केडीबी के सचिव मदन मोहन छाबड़ा, केबीडी के सीईओ चंद्रकांत कटारिया, केडीबी सदस्य उपेंद्र सिंघल सहित हजारों श्रद्धालु यज्ञ और शोभायात्रा में शामिल हुए।

गौरतलब है कि गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष भारत से बाहर विदेशों में गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले मॉरिशस और इंग्लैंड में भी गीता महोत्सव आयोजित किए जा चुके हैं। इस बार यह कार्य‘म कनाडा में आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2016 से गीता महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक, कला एवं संस्कृति का बेजोड़ उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कनाडा की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणावासियों के लिए गर्व की बात है। कनाडा के लोगों की गीता के प्रति आस्था और उत्साह का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। गीता एक ऐसा अलौकिक प्रकाश पुंज है, जो काल, देश और सीमाओं से परे है। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की धरती पर ही 5159 वर्ष पहले गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का संदेश दिया। यह ज्ञान भगवान श्रीकृष्ण ने भले ही भारतभूमि पर दिया, लेकिन यह पूरे संसार के लिए है।

स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि वर्तमान समय में भगवत गीता की प्रासंगिकता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हर व्यक्ति को गीता को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता का संदेश हर काल के लिए प्रासंगिक है और यह हज़ारों साल से मानव को प्रेरणा देता रहा है। उन्होंने कहा कि हमें गीता का संदेश दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

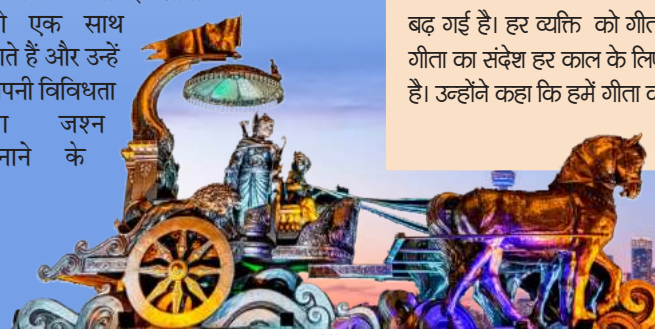

सुण छबीले बोल रसीले

रावण का न मारा जाना

- रसीले, ये बुराई क्या चीज है?

- क्या बात है छबीले, किसी सत्संग से आ रहा है क्या?

- नहीं भाई, मैं सत्संग में कम ही जाता हूं।

- तो क्या कोई गलत वाकया देखा है?

- नहीं रसीले, मैं रामलीला देखकर आया हूं। कल रावण दहन था। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हर साल बुराई के प्रतीक माने जाने वाले रावण, मेघनाथ व अहिरावण को जला दिया जाता है। उसके बावजूद भी लोग बुरे कर्म करने से क्यों नहीं डरते? सत्य है कि बुरे कर्म का परिणाम बुरा होगा तो फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं?

रसीले ने कहा- भाई छबीले, बुराई समाप्त होने वाली चीज नहीं है। यो तो न्यूए चालैगी। रावण समाप्त हो गया तो राम की कद्र कैसे होगी? रावण है, तभी तो राम है। रावण के बिना राम के क्या मोल?

-रसीले, मैं समझा नहीं?

-भाई छबीले, यही सत्य है, अटल सत्य। प्राचीन ग्रंथों में लिखे के मुताबिक यह ब्रह्मांड तीन शक्तियों द्वारा संचालित हो रहा है। रजस, तमस और सत्व। वैज्ञानिक लहजे में इनको पोजिट्रोन, न्यूट्रोन और इलेक्ट्रोन कहा जाता है। धार्मिकता के भाव में जानें तो इन्हे क्रमशः ब्रह्मा, महेश व विष्णु भी कहा जाता है। इन तीन शक्तियों के संतुलन से यह सृष्टि गतिमान है। थोड़ा और देसी लहजे में जानें तो इन्हें ही स्वर्ग, नरक और मोक्ष कह दिया जाता है।

- वाह, कुछ और खोलकर बता रसीले।

- सृष्टि के संचालन के लिए ये तीनों तत्व अनिवार्य हैं। रजस यानी गति, जिसे हम सकारात्मकता एवं अच्छाई भी कह सकते हैं। माना कोई गाड़ी है, वह गाड़ी तभी है जब वह चलायमान है। और अगर उसमें ब्रेक यानी तमस गुण न हो तो वह कहीं रुके ही ना। चलती ही रहेगी। अगर आदमी चलता ही रहे, तो उसके चलने का औचित्य ही क्या रह जाएगा? गति और अगति के मायने ही नहीं रह जाएंगे। रुकना जरुरी है। गति के लिए ब्रेक जरुरी है।

अब यहां तक दो पहलू तो हो गए- रजस व तमस। तीसरा रह गया सत्व। वह है गाड़ी का ड्राइवर। ड्राइवर इन दोनों पर नियंत्रण रखता है। वही गाड़ी को जरुरत अनुसार गति देता है और ब्रेक लगाता है। गाड़ी के संचालन के लिए तीनों तत्व आवश्यक हुए।

- अब सवाल यह है कि अगर संचालन सही है तो लोग गिरते-पड़ते क्यों हैं?

- इसकी वजह है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वार्षण। अगर संभल कर कदम नहीं बढ़ाएंगे तो

पृथ्वी का गुरुत्वार्षण गिरा देगा। चोट भी लग सकती है और टांग भी टूट सकती है। हम सब तेज दौड़ सकते हैं लेकिन संतुलन बनाकर। संतुलन नहीं होगा तो बुराई के खड्ढे में अवश्य पड़ेंगे।

-रसीले, मैंने पूछा है ये बुराई क्या है। आदमी बुराई क्यों करता है?

- जिस प्रकार सृष्टि में ये तीनों तत्व मौजूद हैं, उसी प्रकार आदमी के भीतर भी ये तीनों तत्व विद्यमान हैं। आदमी का जिस ओर झुकाव हो जाता है वह वैसा ही बन जाता है। रजस यानी सकारात्मक रहेगा तो शांति, प्रगति एवं खुशहाली को प्राप्त होगा। थोड़ा और आगे बढ़ा तो संत-महात्मा की श्रेणी को प्राप्त कर लेगा। अगर तमस यानी नकारात्मक रहा तो परेशानियों से रूबरू होगा। जीवन में केवल निराशा एवं हताशा होगी। और अगर दोनों में संतुलन बनाकर चला, समभाव में रहा तो निश्चिंतता रहेगी, बेफिक्री रहेगी। गाड़ी नियंत्रण में चलेगी।

अब यह आदमी पर निर्भर करता है कि वह अपने अंदर ब्रह्मा, महेश अथवा विष्णु, किसको तरजीह देता है। आदमी के भीतर पहले से प्रेम भी मौजूद है और क्रोध भी। अच्छाई भी और बुराई भी। आपका इलेक्ट्रोन यानी सत्व तत्व कितना मजबूत है यह आपकी सोच, संस्कार एवं जीवनशैली पर निर्भर करता है।

- रसीले, कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर राम भी है और रावण भी। और इनके अलावा शिव भी, जिसकी दोनों पूजा किया करते थे। बस संतुलन बनाकर चलना है।

- हां छबीले, अपने ऊपर अवगुणों को हावी न होने दें तो भी जीवन का ठीक से निर्वहन हो जाता है। अवगुण का मतलब क्रोध, लालच, परनिंदा, अहंकार, आलस्य आदि। ये सब न्यूट्रोन यानी विध्वंसकारी महेश के प्रतीक हैं।

- तो भाई छबीले, रावण तो रामलीला का अनिवार्य पात्र है। यह कहीं नहीं जाने वाला। राम रहेगा तो रावण भी रहेगा। इन दोनों के बिना लीला संभव ही नहीं है। जरुरत है अपने-अपने हिस्से के राम को जागृत रखने की, उसकी निरंतर अराधना करने की।

जय श्री राम।

-मनोज प्रभाकर

आया दशहरा

विजय सत्य की हुई हमेशा,
हारी सदा बुराई है,
आया पर्व दशहरा कहता
करना सदा भलाई है।
रावण था दंभी अभिमानी,
उसने छल -बल दिखलाया,
बीस भुजा दस सीस कटाये,
अपना कुनबा मरवाया।
अपनी ही करनी से लंका
सोने की जलवाई है।
मन में कोई कहीं बुराई
रावण जैसी नहीं पले,
और अंधेरी वाली चादर
उजियारे को नहीं छले।
जिसने भी अभिमान किया है,
उसने मुंह की खायी है।
आज सभी की यही सोच है,
मेल-जोल खुशहाली हो,
अंधकार मिट जाए सारा,
घर-घर में दिवाली हो।
मिली बड़ाई सदा उसी को
जिसने की अच्छाई है।

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com